भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें

भरतपुर व बीकानेर यू.आई.टी. होंगे विकास प्राधिकरण, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगी भर्ती

- वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया मुख्यमंत्री ने
- एन.एफ.एस.ए. के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेण्डर
- 1 सितंबर 2024 से लागू होंगी वेतन विसंगति संबंधी सिफारिशें
- बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपये
- द्रव्यवती नदी के विकास के लिए नवीन योजना बनाई जाएगी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर की योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर दिया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल श्रेणी के परिवारों को इसका लाभ मिल रहा था।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान गत सरकार में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करने, पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में अग्निवीर युवाओं को नियुक्ति का प्रावधान, भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीब, पिछड़ा एवं अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए 24 गुणा 7 कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी सर्वजनहिताय की सोच वाला, समाज के सभी वर्गों-युवा, किसान, महिला, मजदूर, गरीब, असहाय, उपेक्षित और अंतिम छोर पर खडे.व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट दिया है। इस बजट के 10 संकल्पों से हम प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ विकसित राजस्थान का निर्माण करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र में काला दिवस था। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने अपना पद बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की। नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में डाला, न्यायालय के अधिकारों पर कुठाराघात किया और मीडिया पर सेंसरशिप लागू की। साथ ही 1953 से 2014 के बीच 50 बार से अधिक राज्यों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनहित का काम करती है, नाम बदलने का राजनीति नहीं। पूर्ववर्ती सरकार ने अटल सेवा केन्द्र का नाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र करने एवं अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना करने का कार्य किया गया।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ठोस कार्य करने की नीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं पूर्ववर्ती सरकार के समय में केवल थोथी घोषणाएं हुईं। पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया गया। वहीं प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के कार्य, जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई, केन्द्रीय बस स्टैंड-सिंधी कैम्प को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में 45 हजार से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित किये हैं। लगभग 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) के लिए भी कोई एमओयू नहीं किया गया। साथ ही, यमुना जल समझौते के लिए एक मांग पत्र भी नहीं लिखा गया। वहीं हमनें प्रदेशहित में इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया।

इस दौरान शर्मा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 के अंतर्गत प्रदेश की ढाई हजार से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 1 हजार 100 करोड़ रुपये के अधिक की राशि के कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में 1 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 10 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 के स्थान पर 1000 ई-बस उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर एवं बीकानेर यूआईटी का उन्नयन कर वहां विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सम्पादित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि द्रव्यवती नदी के विकास के लिए नवीन योजना बनाई जाएगी। उन्होंने 10 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों एवं निकटवर्ती गांवों को शामिल करते हुए 100 कलस्टरों में चरणबद्ध रूप से फेकल स्लज मैनेजमेंट के कार्य एवं दौसा शहर में सीवरेज मास्टर प्लान, सूरजगढ़ (झुंझुनूं), सांगोद (कोटा) में सीवरेज लाईन के कार्य, चेचट एवं खैराबाद कस्बों में क्षतिग्रस्त नालों की सफाई एवं पुनर्निर्माण कार्यों की घोषणा भी की।

शर्मा ने प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु बीसलपुर पेयजल योजना में अजमेर (फेज-3)-जयपुर (फेज-2) के लिए कॉमन इंटेक वैल मय ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण सहित पेयजल संबंधी 9 कार्य 540 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए वाटर टेस्टिंग लैब्स को राष्ट्रीय स्तर का बनाकर एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने हेतु 15 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही, वाटर टेस्टिंग सेंपल्स को जीओ टेगिंग कर ऑनलाइन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए एससीआईएल और गेल से एमओयू करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता का सृजन किया जाएगा। उन्होंने किसानों के खेत पर कुसुम परियोजना/हैम मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किए जाने की घोषणा की। साथ ही, प्रदेश में हैम मॉडल पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से चरणबद्ध रूप से 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने एवं विभिन्न क्षमता के 4 जीएसएस स्थापित किए जाने की घोषणा भी की।

शर्मा ने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किए जाने, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दस्ताकारों को दिये जा रहे 5 प्रतिशत की दर पर ऋण हेतु 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिये जाने, खुशियारा (बारां) एवं पण्डेर (जहाजपुर)-शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में आईटी पार्क स्थापित किये जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की स्किलिंग एवं अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम पेकेज के अंतर्गत प्रदेश के ढाई लाख से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने भर्तियों में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन विभागीय स्तर पर कराये जाने एवं विज्ञप्ति उपरांत रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के नियमों में परिवर्तन किया जाकर इन पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने सीईटी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए क्वालीफिकेशन हेतु सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत एवं एससी-एसटी के लिए 35 प्रतिशत अंक किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कालवाड़, बनीपार्क (जयपुर) सहित 6 नवीन महाविद्यालयों, 3 नवीन कन्या महाविद्यालयों, बालाहेड़ा (महवा-दौसा) में कृषि महाविद्यालय, 2 पॉलिटेक्निक एवं एक महिला पॉलिटेक्निक सहित शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की।

शर्मा ने कहा कि आरयूएचएस का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम-2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने श्रीगंगानगर एवं मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों के लिए लीनियर एक्सलरेटर मशीनें उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाने सहित विभिन्न आस्था केन्द्रों, पेनोरमा एवं बावड़ी संबंधी विकास कार्यों के लिए भी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे। उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि से 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने के लिए विभिन्न सिंचाई संबंधी कार्यों करवाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल, फसली रोग एवं विपणन संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान कर राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। उन्होंने पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि, 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोलने, पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन, परबतसर (डीडवाना-कुचामन), सेड़वा (चौहटन) एवं भाड़ोती (सवाईमाधोपुर) में कृषि मंडी खोलने तथा 150 बीज बैंकों की स्थापना सहित विभिन्न घोषणाएं की।

शर्मा ने केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तर्ज पर अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश में 100 सीटर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर की स्थापना करने, तिजारा (खैरथल) में बॉर्डर होमगार्डस की एक कंपनी तैनात किए जाने, अजमेर/जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किये जाने, डीड राइटर्स की संख्या दोगुनी कर 5 हजार किये जाने, विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाईयों एवं न्यायालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी शेष सिफारिशों को 1 सितंबर, 2024 से लागू करने, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हॉयरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की घोषणा की। उन्होंने पेंशनर्स को राहत प्रदान करते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की।

बोनस अंक नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर। हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 में अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित स्थानीय सीएमएचओ से जवाब तलब किया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश रजनीश भारती की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम किया था। उसके पास करोना काल और उसके बाद का अनुभव प्रमाण पत्र है। इसके बावजूद भी उसे अनुभव के बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया और दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

पांच जिलों में चांदीपुरा वायरस के लिए अलर्ट

जयपुर। गुजरात से सटे जिलों में इन दिनों चांदीपुरा वायरस का खतरा बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से डूंगरपुर, उदयपुर के एरिया में पॉजिटिव केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 5 जिलों के सीएमएचओ को अलर्ट भेजकर संदिग्ध एरिया में मॉनिटरिंग व सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी इसकी जांच शुरू हो गई है। जयपुर में अब तक इसके चार संदिग्ध मरीजों की जांच की जा चुकी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस महीने चांदीपुरा वायरस के पॉजिटिव केस मिलने के बाद से अब तक 13 संदिग्ध मरीजों के सैंपल सीमावर्ती जिलों से पुणे भिजवाएं है। जिनमें से 1 की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव आया 3 साल का ये बच्चा अभी डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी तबीयत अब ठीक है। वहीं, 8 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। शेष की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। डॉ. शर्मा ने बताया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर, सिरोही जिलों के सीएमएचओ को विशेष रूप से एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों में ही सबसे ज्यादा इस वायरस के फैलने की आशंका है। जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बताया कि ये वायरस सबसे ज्यादा मच्छर और मच्छी के काटने से फैलता है। अभी इसका खतरा फिलहाल गुजरात से लगते जिलों में है। इस बीमारी में बच्चे के एकदम से तेज बुखार तो आता ही है साथ में उल्टी-दस्त की शिकायत रहती है। इसके अलावा बच्चों में अचानक बेहोश होने और दौरे पड़ने की भी स्थिति आती है। डॉ. माथुर ने बताया कि इस वायरस की मोर्टलिटी रेट भी 20 से 40 फीसदी के बीच है, जो बहुत ज्यादा है। जयपुर में इस तरह के लक्षण वाले बच्चों जो जे.के. लोन हॉस्पिटल में आ रहे है। उनकी डॉक्टर मॉनिटरिंग कर रहे है। ऐसे संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर उनकी टेस्टिंग भी करवा रहे है। राजधानी जयपुर में इस तरह के चार संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज आ चुके है। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर प्रोफेसर डॉ. भारती मल्होत्रा ने बताया कि ये सैंपल जयपुर के जे. के. लोन से आए थे।

नव नियुक्त राज्यपाल कल शपथ लेंगे

जयपुर। राजस्थान के नव नियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे 31 जुलाई को राजभवन में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल बागडे को मुख्य न्यायाधिपति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव शपथ ग्रहण करवाएंगे। राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में सांय 4 बजे आयोजित होगा।

खिलाड़ी लाल बैरवा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया

जयपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था। हजारों की संख्या में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेता और कार्यकर्ताओं का अब 4 महीने के भीतर ही भाजपा से मोहभंग होने लगा है। कई कार्यकर्ताओं के बाद अब बड़े नेताओं ने भी भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया है।

इसी कड़ी में पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। बैरवा ने अपना इस्तीफा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नाम पत्र लिखकर दिया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लगातार भाजपा से दूरी का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा छोड़ भाजपा की विचारधारा से नहीं जुड़ पा रहा हूं। खिलाड़ी लाल बैरवा ने अपने इस्तीफे में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री (कांग्रेस) की ओर से अपने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की लालसा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को कांग्रेस से बाहर करने का विफल प्रयास किया। सचिन पायलट के गुट के लोगों के फोन टेप करवाए, जिसका लोकेश शर्मा (ओ.एस.डी., पूर्व मुख्यमंत्री) सविस्तार बता चुके है। इनमें मेरा भी फोन टेप करवाया गया, जो कि जांच का विषय है। योजनाबद्ध तरीके के साथ मुझे भी पार्टी से निकाला गया, कुछ खास चापलूसों की सिफारिश पर राजस्थान के इतने टुकड़े-टुकड़े कर दिए। बैरवा ने कहा कि पंचायत समिति स्तर के क्षेत्रफल वालों को जिले बना दिए, समाज के टुकड़े कर इतने सामाजिक बोर्ड बना दिए, जिनका स्वयं को भी पता नहीं। 18 फीसदी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आयोग को वैधानिक दर्जे की बात की तो क्या गुनाह कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री के इस तरह के फैसलों की वजह से कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी मैं भाजपा की विचारधारा से खुद को जोड़ नहीं पा रहा। मैंने 33 वर्ष कांग्रेस में सक्रिय राजनीति की है, यह मेरे खून में है।

खुले में मांस बेचने पर 5 दुकान सीज

जयपुर। हैरिटेज निगम की पशु प्रबंधन शाखा ने सोमवार को बिना लाइसेंस व खुले में मीट बेचने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 दुकानें सीज की है। हैरिटेज निगम के पशु प्रबंधन शाखा उपायुक्त राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि हैरिटेज निगम की ओर से बिना लाइसेंस और खुले में मांस बेचने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को निगम टीम ने गुर्जर की थडी, न्यू सांगानेर रोड पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों पर खुले में मीट बेचा जा रहा था। जिस पर कार्रवाई करते हुए मीट की पांच अवैध दुकानों को सीज किया।

सलूम्बर में दलित शिक्षक और सीकर में दलित छात्र की हत्या का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

कांग्रेस विधायकों ने वैल में उतरकर करीब साढ़े 3 घंटे तक हंगामा और नारेबाजी की, हालात इतने बिगड़े कि सदन की कार्यवाही भी 3 बार स्थगित करनी पड़ी

- विपक्ष का कहना था कि, ''उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद उसके परिजनों को 1 करोड़ रु. मुआवजा और नौकरी दी गई थी, जबकि इस प्रकरण में पीड़ित परिवार को मात्र 21 लाख रु. दिये गए हैं, जो कि भेदभाव है।''
- सदन में यह प्रकरण बढ़ता देखकर स्पीकर देवनानी ने व्यवस्था दी कि, ''राज्य सरकार, मंगलवार को इन मुद्दों पर शून्यकाल के बाद जवाब देगी। इसके बाद हंगामा शांत हुआ और सदन की कार्यवाही सुचारु चली।''

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। सलूम्बर में दलित शिक्षक और सीकर में दलित छात्र की हत्या का मुद्दा सोमवार को विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस विधायकों ने वैल में उतरकर करीब साढ़े 3 घंटे तक हंगामा और नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़े की सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। मामला बढ़ता देखकर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था दी कि, ''राज्य सरकार, मंगलवार को इन मुद्दों पर शून्यकाल के बाद जवाब देगी। इसके बाद हंगामा शांत हुआ और सदन की कार्यवाही सुचारु चली।''

दरअसल शून्यकाल में विधायक थावरचंद ने स्थगन प्रस्ताव के तहत, संलबूर में दलित शिक्षक की हत्या का मामला उठाया और कहा कि इस मामले में पीड़ित परिवार को मात्र 21 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया हैं, जो कि बहुत कम है। थावरचंद ने कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राज्य सरकार ने उसके परिजनों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा एवं एक आश्रित को नौकरी दी थी, जबकि इस मामले में सरकार ने भेदभाव किया है। इस मामले में भी पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाये।

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित विपक्ष के सदस्य भी खड़े हो गए और बोलने लगे, इससे सदन में शोरगुल हुआ। विपक्ष के सदस्य इस मामले को लेकर वेल की तरफ बढने लगे और सदन में हंगामा होने लगा। इस दौरान स्थगन प्रस्ताव के जरिए विधायक पितराम सिंह काला ने सीकर में दलित छात्र की हत्या का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष के सभी सदस्य, दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को लेकर सदन की वैल में आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में हंगामा बढ़ गया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हंगामा कर रहे सदस्यों को टोका लेकिन विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते रहे। देवनानी ने हंगामा कर रहे विपक्ष के सदस्यों से कहा कि संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल जवाब दे रहे हैं, सभी सदस्य अपनी जगह पर जाये लेकिन विपक्ष के सदस्य वैल में डटे रहे और हंगामा करते रहे। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के सदस्य जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, ये सदन में हंगामा मचाना चाहे रहे है।

इस दौरान जोगाराम पटेल जवाब देने के लिए खड़े हुए लेकिन कांग्रेस विधायकों के हंगामे के कारण वापस बैठ गए। हंगामा कम नहीं होता देख जोगाराम पटेल फिर उठे और उन्होंने कहा कि सीकर में छात्र की हत्या के मामले की जांच कराकर 1-2 दिन में इस मामले की पूरी रिपोर्ट सदन को बता दी जायेगी। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा चलता रहा। इसी बीच पर्ची के माध्यम से विधायक गणेशराम बंसल, आदूराम मेघवाल, रामसहाय वर्मा और हरलाल सिंह सहारण ने अपनी बात रखी, लेकिन हंगामे के कारण उनकी कोई भी बात स्पष्ट रुप से सुनाई नहीं दी।

दलित अत्याचार का यह हंगामा बढ़ता देखकर स्पीकर देवनानी ने सदन की कार्यवाही 12:45 बजे (भोजन अवकाश से 15 मिनट पहले) ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर शुरु होने लगी तो कांग्रेस विधायक वैल में हंगामा करते रहे, इसके चलते सभापति संदीप शर्मा ने 2:06 बजे सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी। वापस सदन शुरू होने के बाद भी गतिरोध बरकरार रहा तो पुन: 30 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

बाद में दोपहर 3 बजकर 6 मिनट पर सदन की कार्यवाही को शुरू करवाते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था दी कि, राज्य सरकार इस प्रकरण पर मंगलवार को शून्यकाल के बाद जवाब देगी। इसके बाद सदन में हंगामा शांत हुआ और कार्यवाही सुचारु चली।

आई.एन.ए. सोलर का कॉर्पोरेट ऑफिस जयपुर में शुरू हुआ

जयपुर। क्लीन व ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में भारत की प्रतिष्ठित सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ''इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेड'' (आई.एन.ए. सोलर) ने 28 जुलाई 2024 को न्यू आतिश मार्केट एक्सटेंशन स्थित अपने कॉर्पोरेट ऑफिस ''फ्लुइडकॉन हाउस'' का उद्घाटन किया। दफ्तर का उद्घाटन जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, आई.एन.ए. सोलर के चेयरमैन मनीष गुप्ता व एम.डी. विकास जैन ने किया। कंपनी चेयरमैन मनीष गुप्ता और प्रबंध निदेशक विकास जैन ने बताया कि अब जयपुर स्थित इस कार्यालय पर कंपनी के सभी डिपार्टमेंट के 100 से अधिक कर्मचारी एक साथ बैठ सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह नया कार्यालय हमारे व्यापार के विस्तार का हिस्सा है और इसका उद्देश्य हमारे ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना और हमारे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करेगा।

सरकारी योजनाओं व कैशलेस इलाज में फ़र्ज़ीवाड़े का आरोप

जयपुर। चिकित्सक की अनुपस्थिति में चिकित्सक के डॉक्यूमेंट विभाग में लगाकर सरकारी योजनाओं में मरीज़ों के इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा कर खिलवाड़ किया जा रहा है।

प्राईवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी के प्रेसिडेंट डॉ विजय कपूर ने बताया कि यह अत्यंत गंभीर मामला है। ये कैसे और क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, यह जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरण उनके संज्ञान में लाए गए हैं, जो ज़्यादातर अप्रशिक्षित या झोलाछाप व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं। डॉ. कपूर ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे खुलेआम धड़ल्ले से सरकारी योजनाओं में ये गोरखधंधा चल रहा है। ऐसे में कैसे कोई नैतिकता से काम करने वाले चिकित्सक, अस्पताल सम्मान जनक और सही तरीक़े से इन योजनाओं में काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी जानते हुए भी ऐसे प्रकरणों में कार्रवाई क्यों नहीं करते, यह समझ से परे है।

सरकार ने राजस्थान के हक और अधिकार दिल्ली में गिरवी रख दिए : नेता प्रतिपक्ष

जयपुर। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के बजट को नया कवर चढ़ाकर पेश किया है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि, सरकार ने राजस्थान के हक और अधिकार दिल्ली में गिरवी रख दिए हैं।

टीकाराम जूली ने कहा कि हमारी सरकार जरूरतमंद परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही थी। आपने 450 रुपए कर दिए। आपने जनवरी से आज तक इंदिरा रसोई का अनुदान नहीं दिया। हमने बजट में जयपुर मेट्रो फेज-2 की घोषणा की थी। आपने भी वापस यही घोषणा कर दी। ईआरसीपी के लिए हमने 13,500 करोड़ की घोषणा की थी। आपने उसी घोषणा को टुकड़ों में कर दी। नेता प्रतिपक्ष टीमाराम जूली ने कहा कि केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थी दो बार राजस्थान ने 25 सांसद भाजपा को दिए इस बार भी 14 सांसद दिए लेकिन केंद्रीय बजट में कुछ नहीं मिला। सरकार बचाने के लिए केंद्र का सारा बजट आंध्र और बिहार ले गए। उन्होंने कहा, डॉक्ट्र किरोडी लाल मीणा ने मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह मंजूर नहीं हुआ। किरोड़ीजी अधिकारी के पास गए। क्या प्रोटोकॉल रहा, सरकार जवाब दे। वहां किरोड़ीलाल मीणा नहीं बल्कि पूरी सरकार गई है। जूली ने कहा कि पीएम ने राजस्थान जैसे शांत प्रदेश की तुलना जलते हुए मध्यप्रदेश से की थी। आज की वित्त मंत्री ने तब दिल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया था। आज प्रदेश में महिला अपराध और दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। वित्त मंत्री कब बोलेंगी?

कोचिंग संस्थानों की रिपोर्ट मांगी

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सभी थानाधिकारियों को शहर में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की बिल्डिंग व बैसमेंट में जल भराव एवं अग्नि संबंधी आपदा से संबंधित नियमानुसार सुरक्षा प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था कुंवर राष्ट्रदीप ने सभी थानाधिकारियों को निर्देश जारी कर दो दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर में रहने वाल सभी अभिभावक एवं छात्र व छात्राएँ भी अपने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा संबंधित समस्या से जयपुर पुलिस को सूचना देकर अवगत करवा सकते है। इसके लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष, जयपुर के टोल फ्री नम्बर 100, 112 पर कॉल कर सकते है।

डॉक्टर्स म्यूजिक प्रीमियम लीग संपन्न

जयपुर (कासं)। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 28 जुलाई को डॉक्टर्स की 3 दिवसीय गायन प्रतियोगिता एस.बी.आई. डॉक्टर्स म्यूजिक प्रीमियम लीग सीज़न- 3 ग्रैंड फिनाले के साथ संपन्न हुई। प्रतियोगिता के चैयरमेन डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया कि विजेताओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसबीआई बैंक के डीजीएम व सीडीओ कल्याण गजवेली, गेस्ट ऑफ़ ऑनर एमिटी यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. अमित जैन व बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने ट्रॉफ़ी प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर दर्शकों की मांग पर उपाध्याय ने अपनी प्रस्तुति दी। लीग के आयोजन सचिव डॉ. अनिल यादव ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता में कुल आठ टीमों के 64 गायकों ने 3 दिनों तक प्रतिस्पर्धा करते हुए एक से बढ़कर एक दमदार प्रस्तुतियां दीं। लीग संयोजक डॉ. संदीप निझावन ने बताया कि फाइनल मुकाबले में प्रथम स्थान पाकर टीम आँगन मेडिनोवा ने बाज़ी मारी।